



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ ज्येष्ठ 5, 1939

No. 418]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

गृह मंत्रालय

(सी.एस. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

**सा.का.नि. 517(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कैदियों का संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध ऑस्ट्रेलिया पर लागू होंगे। दण्डादेशित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को हस्ताक्षरित करार का सम्पूर्ण पाठ नीचे दिया गया है। करार अनुसमर्थन की लिखत पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.12.2015 को और ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा दिनांक 21.11.2016 को हस्ताक्षर किए गए।

**दण्डादेशित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार तथा ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच करार**

भारत गणराज्य की सरकार तथा ऑस्ट्रेलिया की सरकार ("संविदाकारी देश");

संविदाकारी देशों के विधि प्रवर्तन के संबंध में लागू विधियों एवं विनियमों तथा विधि प्रवर्तन एवं न्याय के प्रशासन में उनके सहयोगी प्रयासों को बढ़ाने की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए;

शास्तिक दण्डों के प्रवर्तन में सहयोग की अभिलाषा से; और

दण्डादेशित व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास और पुनर्एकीकरण को सुगम बनाने की अभिलाषा से;

निम्न प्रकार से सहमत हो गई हैं :

**अनुच्छेद 1**

**परिभाषाएं**

इस करार के प्रयोजन के लिए:

(क) "निर्णय" से तात्पर्य न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी ऐसे निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;

- (ख) “प्राप्तकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसके क्षेत्राधिकार में दण्डादेशित व्यक्ति को सज़ा अथवा शेष सज़ा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) “दण्ड” से तात्पर्य ऐसे किसी दण्ड या उपाय से है, जिसमें न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य द्वारा अपने दाण्डिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आदेशित निर्धारित समयावधि के लिए या आजीवन कारावास से आजादी से वंचित करना शामिल हो;
- (घ) “दण्डादेशित व्यक्ति” से तात्पर्य किसी दाण्डिक न्यायालय, जिसमें संविदाकारी देशों के क्षेत्राधिकार में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित न्यायालय भी शामिल हैं, द्वारा पारित किसी निर्णय के तहत कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति से है, और इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसको सशर्त रिहा किया गया है या जिस पर निलंबित सज़ा अधिरोपित की गई है; और
- (ङ.) “अंतरणकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसके क्षेत्राधिकार से दण्डादेशित व्यक्ति अंतरित किया जा सकता हो या अंतरित कर दिया गया हो।

## अनुच्छेद 2

### सामान्य सिद्धांत

- (1) संविदाकारी देश इस करार के प्रावधानों के अनुसार दण्डादेशित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में एक-दूसरे को व्यापक सहयोग प्रदान करने का वचन देते हैं।
- (2) इस करार के प्रावधानों के अनुसार किसी अंतरणकर्ता देश के भू-भाग से दण्डादेशित व्यक्ति को उसे दी गई सज़ा काटने के लिए प्राप्तकर्ता देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है।

## अनुच्छेद 3

### सक्षम प्राधिकारी

- (1) संविदाकारी देशों की ओर से इस करार से कार्यान्वयन के लिए प्रभारी सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:  
ऑस्ट्रेलिया के लिए : ऑस्ट्रेलिया सरकार का अटार्नी जनरल विभाग  
भारत गणराज्य के लिए : गृह मंत्रालय
- (2) संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रावधानों के अनुसार अंतरण के लिए अनुरोधों पर कार्रवाई करेंगे।
- (3) सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनों के लिए एक-दूसरे से सीधे संवाद कर सकते हैं।
- (4) यदि कोई संविदाकारी देश अपना सक्षम प्राधिकारी बदलता है, तो वह दूसरे देश को राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित में उक्त परिवर्तन के बारे में अधिसूचित करेगा।

## अनुच्छेद 4

### अंतरण की शर्तें

इस करार के अंतर्गत किसी दण्डादेशित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अंतरित किया जा सकता है:

- (क) ऐसे कृत्य अथवा चूक, जिनके लिए, सज़ा अधिरोपित की गई है, प्राप्तकर्ता देश के कानून के अनुसार दाण्डिक अपराध है, या एक दाण्डिक अपराध होगा, यदि अंतरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने के दिन प्राप्तकर्ता देश के क्षेत्राधिकार के भीतर किया गया हो। यदि दोनों संविदाकारी देश सहमत हों तो विशिष्ट मामले में इस अपेक्षा से छूट दी जा सकती है;
- (ख) जहां भारत प्राप्तकर्ता देश है, दण्डादेशित व्यक्ति भारत का नागरिक हो;
- (ग) जहां ऑस्ट्रेलिया प्राप्तकर्ता देश है, दण्डादेशित व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हो। इस करार के प्रयोजनार्थ किसी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक में एक ऐसे व्यक्ति को शामिल माना जाता है जिसको ऑस्ट्रेलियाई कानून के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में यात्रा करने, प्रवेश करने और अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति हो और जिसका ऑस्ट्रेलिया के किसी राज्य या राज्य-क्षेत्र के साथ सामुदायिक संबंध है बशर्ते कि वह एक भारतीय नागरिक नहीं है;

- (घ) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के दिन, दण्डादेशित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली सज़ा की अवधि कम से कम छः माह बची हो। इस अपेक्षा से किसी विशेष मामलों में छूट दी जा सकती है यदि दोनों संविदाकारी देश सहमत हों;
- (ङ.) निर्णय अंतिम हो;
- (च) अंतरणकर्ता देश में दण्डादेशित व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य विधिक कार्यवाहियां लंबित न हो जिनमें उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो;
- (छ) अंतरणकर्ता एवं प्राप्तकर्ता देश अंतरण के लिए सहमत हों;
- (ज) दण्डादेशित व्यक्ति अंतरण के लिए सहमत हो। जहां दण्डादेशित व्यक्ति दोनों में से किसी संविदाकारी देश के कानून के अंतर्गत सहमति देने में अक्षम है, वहां उस संविदाकारी देश के कानून के अनुसार उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी व्यक्ति द्वारा सहमति दी जा सकती है;
- (झ) दण्डादेशित व्यक्ति पर मृत्यु दण्ड अधिरोपित नहीं किया गया है; सिवाय इसके कि मृत्यु दण्ड को कम करके कारावास या आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया हो;
- (ञ) दण्डादेशित व्यक्ति को सैन्य कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है, सिवाय उन परिस्थितियों में जहां संविदाकारी देश अन्यथा सहमत हों; तथा
- (ट) प्राप्तकर्ता देश में दण्डादेशित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;

#### **अनुच्छेद 5**

#### **बहुपक्षीय अभिसमय (कन्वेंशन) के साथ संबंध**

यह करार उन बहुपक्षीय अभिसमय (कन्वेंशन), जिनके कोई एक या दोनों संविदाकारी देश पक्षकार हैं, से उत्पन्न संविदाकारी देशों के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

#### **अनुच्छेद 6**

#### **अंतरण की प्रक्रिया**

- (1) संविदाकारी देश उनकी दोषसिद्धि के बाद इस करार के तथ्य के बारे में दण्डादेशित व्यक्तियों को सूचित करने के लिए जिम्मेदार कदम उठाएंगे।
- (2) यदि दण्डादेशित व्यक्ति अंतरण किए जाने के लिए इच्छा व्यक्त करता है तो वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति, अंतरणकर्ता देश या प्राप्तकर्ता देश से ऐसी इच्छा व्यक्त कर सकता है, जिनमें से कोई एक लिखित में दूसरे संविदाकारी देश को सूचित करेगा।
- (3) किसी दण्डादेशित व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर अंतरणकर्ता देश या प्राप्तकर्ता देश राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित में अंतरण हेतु अनुरोध कर सकता है।
- (4) अंतरण के लिए अनुरोध लिखित में होगा तथा इसमें निम्नलिखित सूचना शामिल होगी:
  - (क) दण्डादेशित व्यक्ति का नाम, उसके जन्म की तारीख तथा जन्म का स्थान;
  - (ख) दण्डादेशित व्यक्ति की नागरिकता, राष्ट्रीयता या आवासीय प्रास्थिति का विवरण; और
  - (ग) दण्डादेशित व्यक्तियों का अवस्थान तथा वर्तमान पता।
- (5) जहां अंतरण के लिए अनुरोध किया गया है, वहां अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना प्रदान करेगा जब तक कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निर्णय नहीं ले लिया हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं होगा:
  - (क) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दोषसिद्धि एवं दण्ड आधारित थे;
  - (ख) अपराध साबित करने वाले संगत कानून का विवरण;
  - (ग) दण्ड, यदि लागू हो, के आरंभ होने एवं समाप्त होने की तारीखें तथा दण्ड की प्रकृति;
  - (घ) दण्डित व्यक्ति द्वारा पहले ही भोगी गई सज़ा की अवधि;

- (ड.) किए गए कार्य, अच्छे व्यवहार, विचारण-पूर्व कैद या अन्य कारणों के आधार पर क्षमादान, जिसके लिए वह हकदार है;
- (च) पहली संभावित तारीख जिस पर दण्डादेशित व्यक्ति रिहाई के लिए पात्र बना था या पात्र होगा या जिस पर रिहाई के लिए विचार किया जाना है, और, रिहाई यदि लागू हो के बाद कोई शर्त या पर्यवेक्षण जिसके अध्यक्षीन दण्डादेशित व्यक्ति है या होगा;
- (छ) दोषसिद्धि एवं दण्ड के प्रमाणपत्र या रिकॉर्ड की प्रति और, यदि लागू हों, किन्हीं निर्णयों एवं दण्ड संबंधी अभ्युक्तियों की प्रतियां;
- (ज) दण्डादेशित व्यक्ति के संबंध में कोई सुधारात्मक सुविधा, चिकित्सीय या सामाजिक रिपोर्टें तथा यदि लागू हो, अंतरणकर्ता देशों में दण्डादेशित व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार, प्राप्तकर्ता देश में आगे के उपचार लिए किसी अनुशंसा के बारे में सूचना; और
- (झ) यथासंभव, कोई अन्य सूचना जिसे प्राप्तकर्ता देश अंतरण की संभावना पर विचार करने और अपने कानून के अंतर्गत दण्डादेशित व्यक्ति के अंतरण के बारे में उसे सूचित करने में स्वयं को सक्षम बनाने के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट करें।
- (6) अंतरणकर्ता देश द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्राप्तकर्ता देश अंतरण से पहले अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना प्रदान करेगा जब तक कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निर्णय नहीं ले लिया हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं होगा:
- (क) एक ऐसा दस्तावेज़ या विवरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि दण्डादेशित व्यक्ति ने अनुच्छेद 4(ख) या 4(ग) में निहित शर्तों का अनुपालन किया है;
- (ख) संगत कानून की एक प्रति और एक विवरण कि ऐसे कृत्य या चूक, जिनके कारण दण्ड अधिरोपित किया गया है, प्राप्तकर्ता देश के कानून के अनुसार दाण्डिक अपराध के अनिवार्य घटक हैं, या जो अंतरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने के दिन, प्राप्तकर्ता देश के क्षेत्राधिकार के भीतर किए जाने पर दाण्डिक अपराध के अनिवार्य घटक होंगे, जब तक कि अनुच्छेद 4(क) में निहित शर्त से छूट नहीं दे दी गई हो;
- (ग) एक ऐसा विवरण जिसमें दण्ड में किए गए किसी अनुकूलन और समय से पहले रिहाई की छूट की संभावित हकदारियों सहित यह वर्णन किया गया हो कि किस प्रकार सतत प्रवर्तन तौर-तरीके (अनुच्छेद 10) के अनुसार प्राप्तकर्ता देश में दण्डादेशित व्यक्ति के दण्ड को प्रवर्तित किया जाएगा;
- (घ) ऐसा विवरण कि ऐसे कृत्यों या चूकों, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में दंड प्रवर्तित किया गया था, के लिए प्राप्तकर्ता देश में दण्डादेशित व्यक्ति का विचारण नहीं किया जाएगा या उनको दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा सिवाय इस करार के अनुसार, उन कृत्यों या चूकों के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा; तथा
- (ड.) यथा संभाव अंतरणकर्ता देश द्वारा प्रार्थित संभावित अंतरण से संगत कोई अन्य अतिरिक्त सूचना।

(7) अंतरणकर्ता देश के प्राधिकारी दण्डादेशित व्यक्ति को दोनों संविदाकारी देशों द्वारा यथा सम्मत तारीख को और अंतरणकर्ता देश के भू-भाग के भीतर किसी स्थान पर प्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारियों को सुपुर्द करेंगे। प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश से दण्डादेशित व्यक्ति के परिवहन के लिए जिम्मेदार होगा तथा अंतरणकर्ता देश के भू-भाग से बाहर दण्डादेशित व्यक्ति की अभिरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा।

### **अनुच्छेद 7**

#### **दण्डादेशित व्यक्ति की सम्मति**

- (1) अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि दण्डादेशित व्यक्ति स्वेच्छा से तथा विधिक परिणामों की पूरी जानकारी के साथ अंतरण के लिए सम्मति प्रदान करे। ऐसी सम्मति प्रदान करने की प्रक्रिया अंतरणकर्ता देश के कानून द्वारा शासित होगी।
- (2) अंतरण से पूर्व, यदि प्राप्तकर्ता देश की इच्छा हो तो अंतरणकर्ता देश उसे यह अवसर प्रदान करेगा कि वह इस बात का सत्यापन करे कि अंतरण के लिए दण्डादेशित व्यक्ति की सहमति अनुच्छेद 4(ज) के अनुसार स्वेच्छा से तथा अनुच्छेद 14(1) के अनुसरण में लागत की वसूली सहित, इसके कानूनी परिणामों की जानकारी के साथ दी जा रही है।

**अनुच्छेद 8****संविदाकारी देशों की सहमति**

दण्डादेशित व्यक्ति के अंतरण के संबंध में संविदाकारी देशों द्वारा लिखित में सहमति प्रदान की जाएगी।

**अनुच्छेद 9****क्षेत्राधिकार**

- (1) अंतरणकर्ता देश इसके न्यायालयों द्वारा लगाई गई दोषसिद्धियों की पुनरीक्षा, उनमें संशोधन, सुधार अथवा उन्हें रद्द किए जाने संबंधी अनन्य क्षेत्राधिकार अपने पास रखेगा।
- (2) अंतरण के उपरांत, संविदाकारी देशों में से कोई भी देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुसार दोष सिद्धियों तथा दण्ड के मामले में माफी, राजक्षमा, दण्ड का लघुकरण अथवा इसमें कमी या इसे माफ कर सकता है तथा इस निर्णय के संबंध में वह अन्य संविदाकारी देश को लिखित रूप में सूचित करेगा।

**अनुच्छेद 10****सजा का सतत प्रवर्तन**

- (1) प्राप्तकर्ता देश दण्ड को इस प्रकार प्रवर्तित करेगा मानो उस दण्ड की अवधि अथवा समाप्त होने की तारीख वही है जो अंतरणकर्ता देश द्वारा निर्धारित की गई हो और मानो कि दण्ड प्राप्तकर्ता देश में लगाया गया हो।
- (2) अंतरण के बाद दण्ड के सतत प्रवर्तन को प्राप्तकर्ता देश के कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित किया जाएगा, जिनमें कारावास, कैद अथवा स्वतंत्रता से अन्य किसी प्रकार से वंचित किए जाने की शर्तों तथा पैरोल, सशर्त रिहाई, माफी द्वारा अथवा अन्यथा कारावास, कैद अथवा अन्य किसी प्रकार से स्वतंत्रता से वंचित किए जाने की अवधि को कम करने के प्रावधान से संबंधित शर्तों को शासित करने वाले कानून और प्रक्रियाएं भी शामिल होंगी।
- (3) यदि, दण्ड का स्वरूप और अवधि प्राप्तकर्ता देश के कानून के अनुरूप नहीं है, तो प्राप्तकर्ता देश उस दण्ड को अंतरणकर्ता देश को समान अपराध के लिए शर्तों का प्रस्ताव करके उसके स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित दण्ड के अनुरूप बना लेगा। दण्ड को अनुरूप बनाते समय, प्राप्तकर्ता देश के उपयुक्त प्राधिकारी, तथ्य के निष्कर्षों, जहां तक वे अंतरणकर्ता देश द्वारा दोषसिद्धि, निर्णय अथवा दिए गए दण्ड से प्रतीत होते हों, से बाध्य होंगे। रूपान्तरित दण्ड, उसके स्वरूप अथवा अवधि की दृष्टि से अंतरणकर्ता देश द्वारा लगाए गए दण्ड से अधिक सख्त नहीं होगा।
- (4) प्राप्तकर्ता देश, जैसे ही उसे अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी निर्णय के बारे में सूचित किया जाए, दण्ड के प्रवर्तन में संशोधन करेगा अथवा उसे समाप्त करेगा।
- (5) संविदाकारी देश अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतरणकर्ता देश द्वारा की गई किसी कार्यवाई अथवा लिए गए किसी निर्णय के बारे में लिखित में दण्डादेशित व्यक्ति को सूचित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

**अनुच्छेद 11****दण्ड के प्रवर्तन के बारे में सूचना**

प्राप्तकर्ता देश दण्ड के प्रवर्तन के बारे में अंतरणकर्ता देश को तभी सूचना प्रदान करेगा

- (क) यदि दण्डादेशित व्यक्ति की सशर्त रिहाई की जाती है;
- (ख) जब वह यह समझे कि दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया है;
- (ग) यदि दण्डादेशित व्यक्ति दण्ड का प्रवर्तन पूरा किए जाने से पूर्व अभिरक्षा से भाग निकला हो; अथवा
- (घ) यदि, अंतरणकर्ता देश ने किसी रिपोर्ट के लिए अनुरोध किया हो।

**अनुच्छेद 12****दण्डादेशित व्यक्ति का पारगमन**

- (1) यदि, दोनों में से कोई संविदाकारी देश दण्डादेशित व्यक्तियों के अंतरण के बारे में किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है, ता दूसरा संविदाकारी देश, अपने देश के कानून के अधीन, अपने भू-भाग से होकर पारगमन को सुगम बनाने में सहयोग करेगा, सिवाय तब जब वह पारगमन के निम्नलिखित स्थिति में इन्कार करे:
  - (क) दण्डादेशित व्यक्ति उसके स्वयं के नागरिकों में से एक हो; अथवा

- (ख) अनुरोध से संविदाकारी देश की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण हित की हानि होती हो।
- (2) ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अग्रिम नोटिस देगा।
- (3) ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश से यह आश्वासन देने के लिए कह सकता है कि पारगमन को सुगम बनाने के प्रयोजन के अलावा दण्डादेशित व्यक्ति पर भिन्न अपराध के लिए अभियोजन नहीं चलाया जाएगा अथवा उसे निरुद्ध नहीं किया जाएगा अथवा तीसरे देश, जिसमें दण्ड लगाया गया हो, के भू-भाग से उसके प्रस्थान से पूर्व किए गए किसी अपराध अथवा उसको दिए गए दण्ड के लिए उसकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

### अनुच्छेद 13

#### भाषा

अनुरोध एवं समर्थनकारी दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में होंगे अथवा उनके साथ अंग्रेज़ी अनुवाद लगाया जाएगा।

### अनुच्छेद 14

#### व्यय

- (1) प्राप्तकर्ता देश निम्नलिखित पर होने वाले व्यय को वहन करेगा:
- (क) दण्डादेशित व्यक्तियों के अंतरण पर, अनन्य रूप से अंतरणकर्ता देश के भू-भाग में हुए व्यय को छोड़कर; और
- (ख) अंतरण के पश्चात दण्ड के सतत प्रवर्तन पर।

तथापि, प्राप्तकर्ता देश दण्डादेशित व्यक्तियों से अंतरण की समस्त अथवा आंशिक लागत को वसूल कर सकता है।

- (2) अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उल्लिखित अनुरोधों, दस्तावेज़ों अथवा सूचना के अनुवाद की लागत अनुरोध, दस्तावेज़ अथवा सूचना भेजने वाले संविदाकार देश द्वारा वहन की जाएगी।

### अनुच्छेद 15

#### परामर्श

इस करार के सर्वाधिक प्रभावी प्रयोग को बढ़ावा देने और ऐसे व्यावहारिक उपायों, जो इस करार के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक हों, से सहमत होने के लिए संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर परामर्श कर सकते हैं।

### अनुच्छेद 16

#### विवादों का निपटारा

- (1) सक्षम प्राधिकारी इस करार की व्याख्या, इसको लागू किए जाने अथवा इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी विवाद को पारस्परिक रूप से हल करने का प्रयास करेंगे।
- (2) यदि सक्षम प्राधिकारी विवाद का पारस्परिक रूप से समाधान करने में असमर्थ हों तो इसका समाधान राजनयिक चैनलों के माध्यम से किया जाएगा।

### अनुच्छेद 17

#### संशोधन

संविदाकारी देशों द्वारा सहमत इस करार में कोई संशोधन अथवा आशोधन इस करार की तरह ही प्रवृत्त होंगे।

### अनुच्छेद 18

#### करार का प्रवृत्त होना और इसे समाप्त करना

- (1) यह करार अनुसमर्थन के अधीन होगा। प्रत्येक संविदाकारी देश इस करार को लागू करने के लिए अपेक्षित अपनी विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित में शीघ्रातिशीघ्र दूसरे देश को इसके बारे में सूचित करेगा। यह करार अंतिम अधिसूचना की तारीख के 30 दिन के बाद प्रवृत्त होगा।
- (2) यह करार इसके प्रवृत्त होने के पूर्व अथवा बाद में लगाए गए दण्डों के प्रवर्तन के लिए लागू होगा।

- (3) यह करार अनिश्चित अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। तथापि, यह करार राजनयिक चैनलों के माध्यम से इसे समाप्त करने का लिखित में नोटिस देकर किसी भी संविदाकारी देश द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसका परिसमापन इस प्रकार के नोटिस की तारीख के छः माह बाद प्रभावी होगा।
- (4) किसी भी परिसमापन के बावजूद, यह करार उस तारीख, जिसको इसका परिसमापन प्रभावी होता है, से पूर्व इस करार के अंतर्गत अंतर्गत दण्डादेशित व्यक्तियों के दण्डों के प्रवर्तन के लिए लागू रहेगा।

इसके प्रमाण स्वरूप अपनी-अपनी सरकारों द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत होने के नाते अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

कैनबरा में 18 नवम्बर, 2014 को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं की मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए, सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। व्याख्या में भेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

आस्ट्रेलिया की  
सरकार की ओर से

ह./-  
(बिरेन नंदा)  
उच्चायुक्त

ह./-  
माइकल कीनन  
न्याय मंत्री  
[फा. सं. V-17011/28/2008-पी आर]  
दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CS Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2017

**G.S.R. 517(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to Australia. The full text of the Agreement on Transfer of Sentenced Persons signed by the Government of the Republic of India and the Government of the Australia on 18.11.2014 is given below. The Agreement was ratified by the Government of India on 16.12.2015 and by the Government of Australia on 21.11.2016.

### AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Government of the Republic of India and the Government of Australia (“the Contracting States”)

Taking into consideration the laws and regulations in force regarding law enforcement of the Contracting States and the desirability of enhancing their co-operative efforts in law enforcement and the administration of Justice;

Desiring to co-operate in the enforcement of penal sentences; and

Desiring to facilitate the rehabilitation and reintegration of sentenced persons into society;

Have agreed as follows:

#### ARTICLE 1

#### DEFINITION

For the purpose of this Agreement:

- (a) “judgment” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) “receiving State” means the State to whose jurisdiction the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his or her sentence or remainder thereof;

- (c) “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court, tribunal or otherwise for a determinate period of time or for life imprisonment in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) “sentenced person” means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgment passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the jurisdiction of the Contracting States, and also includes a person who has been conditionally released or on whom a suspended sentence has been imposed; and
- (e) “transferring State” means the State from whose jurisdiction the sentenced person may be, or has been, transferred.

## **ARTICLE 2**

### **GENERAL PRINCIPLES**

- (1) The Contracting States undertake to afford each other the widest measure of co-operation in respect of the transfer of sentenced persons in accordance with the provisions of this Agreement.
- (2) A sentenced persons may be transferred from the territory of the transferring State to the territory of the receiving State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him or her.

## **ARTICLE 3**

### **COMPETENT AUTHORITIES**

- (1) The Competent Authorities in charge of the implementation of this Agreement for the Contracting States are:  
For Australia: Australian Government Attorney-General’s Department  
For the Republic of India: Ministry of Home Affairs.
- (2) The Competent Authorities of the Contracting States shall process requests for transfer in accordance with the provisions of this Agreement.
- (3) The Competent Authority may communicate directly with each other for the purposes of this Agreement.
- (4) Either Contracting State shall notify the other of any changes of its Competent Authority in writing through diplomatic channels.

## **ARTICLE 4**

### **CONDITIONS FOR TRANSFER**

A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:

- (a) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the receiving State, or would constitute such a criminal offence if committed within the jurisdiction of the receiving State on the day of receipt of the request for transfer. If both Contracting States agree, this requirement may be waived in a specific case;
- (b) where India is the receiving State the sentenced person is a citizen of India;
- (c) where Australia is the receiving State, the sentenced person is an Australian citizen. An Australian citizen, for the purposes of this Agreement, is deemed to include a person who is permitted to travel to, enter and remain indefinitely in Australia in accordance with Australian law and has community ties with a State or Territory of Australia provided he or she is not an Indian citizen;
- (d) on the day of receipt of the request for transfer, the sentenced person has at least six months of the sentence remaining to be served. This requirement may be waived in a particular case if both Contracting States agree.
- (e) the judgment is final;
- (f) no other legal proceedings are pending against the sentenced person in the transferring State in which his or her presence is required;
- (g) the transferring and receiving States agree to the transfer;
- (h) the sentenced person agrees to the transfer. Where the sentenced person is incapable of giving consent under the law of either Contracting State, consent may be given by a person entitled to act on his or her behalf in accordance with the law of that Contracting State;
- (i) the death penalty has not been imposed on the sentenced person, except that the death penalty has been commuted to a term of imprisonment or to life imprisonment.



- (j) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law, except in circumstances where the Contracting States agree otherwise; and
- (k) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State;

### **ARTICLE 5**

#### **RELATIONSHIP WITH MULTILATERAL CONVENTIONS**

This Agreement shall not affect any obligation of the Contracting States arising under multilateral conventions to which one or both Contracting States are party.

### **ARTICLE 6**

#### **PROCEDURE FOR TRANSFER**

- (1) The Contracting States shall take responsible steps to inform sentenced persons of the substance of this Agreement after their conviction.
- (2) If the sentenced person wishes to be transferred, he or she, or someone on their behalf, may express such a wish to the transferring State or the receiving States, either of whom shall inform the other Contracting State in writing.
- (3) Upon receiving an application from a sentenced person, either the transferring or the receiving State may make a request for transfer in writing through diplomatic channels.
- (4) Request for transfer shall be in writing and shall include the following information:
  - (a) the name, date and place of birth of the sentenced person;
  - (b) a statement of the citizenship, nationality or residence status of the sentenced person; and
  - (c) the location of the sentenced persons and current address.
- (5) Where a request for transfer has been made, the transferring State shall provide the receiving State with the following information unless either the receiving or transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
  - (a) a statement of the facts upon which the conviction and sentence were based;
  - (b) a statement of the relevant law creating the offence;
  - (c) the commencement and termination dates of the sentence, if applicable and the nature of the sentence;
  - (d) the length of time already served by the sentenced person;
  - (e) any remission to which he or she is entitled on account of work done, good behavior, pre-trial confinement or other reasons;
  - (f) the first possible date on which the sentenced person became or will become eligible for release or is to be considered for release, and any condition or supervision the sentenced person is subject to or will be subject to on release, if applicable;
  - (g) a copy of the certificate or record of conviction and sentence and, if applicable, copies of any judgments and sentencing remarks;
  - (h) any correctional facility, medical or social reports on the sentenced person and, if applicable, information about the sentenced person's medical treatment in the transferring States any recommendation for further treatment in the receiving State; and
  - (i) as far as possible, any other information which the receiving State may specify as required, to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him or her under its law.
- (6) The receiving State shall provide the transferring State with the following information before transfer, if requested by the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
  - (a) a document or statement indicating that the sentenced person complies with the conditions in Article 4 (b) or 4 (c);
  - (b) a copy of the relevant law and a statement that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute the essential elements of a criminal offence according to the law of the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed within the jurisdiction of the receiving State, on the day of receipt of the request for transfer, unless the condition in Article 4(a) has been waived;

- (c) a statement describing how the sentenced person's sentence would be enforced by the receiving state in accordance with the continued enforcement method (Article 10), including any adaptation made to the sentence and potential entitlements to remissions for early release;
  - (d) a Statement that the sentenced person will not be tried or sentenced in the receiving State for the acts or omission on account of which the sentence was enforced in the transferring State and shall not be detained for those acts or omission except in accordance with this Agreement; and
  - (e) as far as possible, any other additional information relevant to the potential transfer requested by the transferring State.
- (7) Delivery of the sentenced person by the authorities of the transferring State to those of the receiving State shall occur on a date and at a place within the territory of the transferring State as agreed upon by both Contracting States. The receiving State shall be responsible for the transport of the sentenced person from the transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the transferring State.

#### **ARTICLE 7**

##### **CONSENT OF THE SENTENCED PERSON**

- (1) The transferring State shall take reasonable steps to ensure that the sentenced person consents to the transfer voluntarily and with full knowledge of the legal consequences. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.
- (2) Prior to transfer, the transferring State shall afford an opportunity to the receiving State, if the receiving State so desires, to verify that the sentenced person's consent to the transfer in accordance with Article 4 (h) is given voluntarily and with full knowledge of the legal consequences, including recovery of costs in accordance with Article 14 (1).

#### **ARTICLE 8**

##### **CONSENT OF CONTRACTING STATES**

The Contracting States shall consent in writing to the transfer of the sentenced person.

#### **ARTICLE 9**

##### **JURISDICTION**

- (1) The transferring State shall retain exclusive jurisdiction for the review, revision, modification or cancellation of convictions imposed by its courts.
- (2) Following transfer, either Contracting State may grant pardon, amnesty, commutation of, or reductions or remissions to, convictions and sentences in accordance with its Constitution or other laws and shall notify the other Contracting State in writing of this decision.

#### **ARTICLE 10**

##### **Continued enforcement of sentence**

- (1) The receiving State shall enforce the sentence as if the sentence had the same duration or termination date as imposed by the transferring State and as if the sentence had been imposed in the receiving State.
- (2) The continued enforcement of the sentence after transfer shall be governed by the laws and procedures of the receiving State, including those governing conditions for service of imprisonment, confinement or other deprivation of liberty by parole, conditional release, remission or otherwise and those providing for the reduction of the term of imprisonment, confinement or other deprivation of liberty by parole, conditional release, remission or otherwise.
- (3) If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the receiving State, the receiving State may, in proposing terms to the transferring State, adapt the sentence in accordance with the sentence prescribed by its own law for a similar offence. When adapting the sentence, the appropriate authorities of the receiving State shall be bound by the findings of fact, insofar as they appear from the conviction, judgment, or sentence imposed by the transferring State. The adapted sentence shall be no more severe than the imposed by the transferring State in terms of nature or duration.
- (4) The receiving State shall modify or terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed of any decision by the transferring State in accordance with Article 9.
- (5) The contracting States shall take reasonable steps to inform the sentenced person in writing of any action or decision taken by the transferring State in accordance with Article 9.

**ARTICLE 11****INFORMATION ON ENFORCEMENT OF SENTENCE**

The receiving State shall provide information to the transferring State concerning enforcement of the sentence:

- (a) if the sentenced person is granted conditional release;
- (b) when it considers enforcement of the sentence to have been completed;
- (c) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed; or
- (d) if the transferring State requests a report.

**ARTICLE 12****TRANSIT OF THE SENTENCED PERSON**

- (1) If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall, subject to its domestic law, co-operate in facilitating the transit through its territory except that it may refuse to grant transit if the:
  - (a) sentenced person is one of its own nationals; or
  - (b) request may infringe upon the sovereignty, safety, public order or any other essential interest of the Contracting State.
- (2) The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice in writing to the Competent Authority of the other Contracting State.
- (3) The Contracting State intending to make such a transfer may ask the other Contracting State to give an assurance that the sentenced person will not be prosecuted or detained, other than for the purpose of facilitating transit, or otherwise subjected to any restriction on his or her liberty for any offence committed or sentence imposed prior to his or her departure from the territory of the third State in which the sentence was imposed.

**ARTICLE 13****LANGUAGE**

Requests and supporting documents shall be in English or shall be accompanied by a translation into English.

**ARTICLE 14****EXPENSES**

- (1) The receiving State shall bear the expenses of :
  - (a) the transfer of Sentenced persons, except the expenses incurred exclusively in the territory of the transferring State; and
  - (b) the continued enforcement of the sentence after transfer.

The receiving State may, however, seek to recover all or part of the cost of transfer from the sentenced person.

- (2) The costs of translation of requests, documents or information referred to under Article 13 shall be borne by the Contracting State sending the request, document or information.

**ARTICLE 15****CONSULTATION**

The Competent Authorities of the Contracting States may consult with each other to promote the most effective use of this Agreement and to agree upon such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Agreement.

**ARTICLE 16****SETTLEMENT OF DISPUTES**

- (1) The Competent Authorities shall endeavor to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.
- (2) If the Competent Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

**ARTICLE 17****AMENDMENTS**

Any amendments or modifications to this Agreement agreed to by the Contracting States shall come into force in the same manner as the Agreement itself.

**ARTICLE 18****ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION**

- (1) This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedure required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force thirty days after the date of last notification.
- (2) This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed before or after the entry into force of this Agreement.
- (3) The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the Contracting States by giving a written notice of termination through diplomatic channels. The termination shall take effect after six months of the date of such notice.
- (4) Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of sentenced persons transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

**In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments have signed this Agreement.**

**Done in duplicate at Canberra, this 18<sup>th</sup> day of November, two thousand and fourteen, in English and Hindi, each texts being equally authentic. In case of differences in interpretation the English text shall prevail.**

**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF  
AUSTRALIA**

**Sd/-**

**(Biren Nanda)  
High Commissioner**

**Sd/-**

**(Michael Keenam)  
Minister for Justice**

[F. No. V-17011/28/2008-PR]

DILIP KUMAR, Jt. Secy.